मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

# मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 66400/97

| | |
|---|---|
| हार्डवेयर चौक पर सड़क का निर्माण ड्रामा | 3 |
| इन्द्री में किसानों ने भाजपा के विरोध का दिखाया दम | 4 |
| मोदी को अमेरिका यात्रा में हुआ सच का सामना | 5 |
| किसान अन्दोलन की नाव में सवार होने को आतुर चौटाला | 6 |
| ज़िला शिक्षा अधिकारी को चार्जशीट | 8 |

वर्ष 35 | अंक 47 | फरीदाबाद | 3-9 अक्टूबर 2021 | फोन-8851091460 | ₹3.00

# फोगाट स्कूल में एचपीएससी परीक्षा केन्द्र बनने के पीछे हैं उसके वीआईपी अभ्यार्थी

बल्लबगढ़ ( म.मो. ) समयपुर रोड पर स्लम जैसे क्षेत्र में स्थित फोगाट स्कूल, जिसे आम आदमी, खासकर दूसरे शहर से आने वाले लोगों के लिये ढूंढ पाना आसान नहीं, को हरियाणा पब्लिक सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा परीक्षा केन्द्र बनाया जाना एक रहस्य जैसा लगता है। दिनांक 12 सितम्बर को हुई परीक्षा के दौरान कुछ अधिकारियों ने यह सवाल उठाया भी कि ऐसी लोकेशन पर यह सेंटर कैसे बना दिया गया? पूछ-पड़ताल करने पर उन्हें बताया गया कि यह सेंटर तो बीते दिसम्बर जनवरी में ही बना दिया गया था। स्कूलों को सेंटर बनाने का निर्णय ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा लिया जाता है।

जानकार बताते हैं कि इस स्कूल को सेंटर बनाने के लिये राज्य के शिक्षा

अनीता यादव आईएएस
सीईओ एफएमडीए

मंत्री कंवरपाल व तत्कालीन उपायुक्त यशपाल ने तत्कालीन ज़िला शिक्षा अधिकारी सुखविंदर कौर वर्मा को सिफ़ारिश की थी। किसी भी स्कूल को सेंटर बनाने तक तो कोई बात नहीं क्योंकि किसी भी स्कूल को सेंटर बनाने या बनाने सम्बन्धी कोई दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन बात तब समझ में आने लगती है जब अनीता यादव आईएएस की बेटी का सेंटर इसी फोगाट सेंटर में आता है। विदित है कि अनिता यादव बीते कई वर्षों से इसी ज़िले में विभिन्न पदों पर तैनात रही हैं और आज भी यहीं तैनात हैं। और तो और परीक्षा केन्द्रों की निगरानी का जो क्षेत्र इन्हें सौंपा गया था, उसमें फोगाट स्कूल भी आता था। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति की सलाह पर, परीक्षा से चार दिन पूर्व इनका नाम फोगाट सेंटर से हटा दिया गया। लिहाजा जो 'काम' उस क्षेत्र में ड्यूटी लगवा कर करना था वह अब थोड़ा दूर से किया जा सकता है।

चश्मदीद बताते हैं कि उपायुक्त जितेन्द्र यादव फोगाट सेंटर पर गये। वहां कुछ देर स्कूल मालिक के दफ्तर में बैठे जलपान ग्रहण किया। बेशक उन्होंने इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, लेकिन स्थिति तो संदेहास्पद बन ही गयी। संदेह तो होना स्वाभाविक है कि डीसी साहब अनिता की बेटी के लिये कुछ जुगाड़ लगाने गये होंगे।

अनिता यादव की बेटी के अलावा दो बच्चे डीएसपी होडल दिनेश यादव के भी इसी सेंटर में परीक्षा दे रहे थे। दिनेश यादव बतौर इन्स्पेक्टर और डीएसपी काफ़ी समय इस ज़िले में तैनात रह चुके हैं और आज भी इसी क्षेत्र में हैं। परीक्षा में नकल एवं हेरा-फ़ेरी रोकने के नाम पर सरकार जो अभ्यार्थियों को दूर-दराज के ज़िलों में सेंटर एलॉट करती है वह मात्र ढोंग एवं दिखावा है। जिन्हें हेरा-फेरी करानी होती है वे सेंटर भी अपनी मन-मर्जी का बनवाते हैं और उसमें निगरानी स्टाफ़ भी अपनी मर्जी का तैनात कराते हैं। इसकी योजना, सरकार के सहयोग से ये लोग बहुत पहले से ही बना लेते हैं। इस तरह की हेरा-फ़ेरी कोई पहली बार नहीं हो रही।

हर सरकार अपने चहेतों व लग्गुए-भग्गुओं के बच्चों को इसी तरह परीक्षा पास करा कर अधिकारी बनाती रही है। ऐसा भी उदाहरण चर्चा में रहा है, जब अभ्यार्थी की जगह पर्चा लिखने किसी और को ही बैठा दिया गया था।

# शराब का अवैध धंधा पुलिस के संरक्षण में ही चल सकता है

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** शराब की अवैध बिक्री को लेकर सीपी विकास अरोड़ा की ओर से जारी किये गये एक बयान में कहा गया है कि सम्बन्धित क्षेत्रों के एसीपी नियमित रूप से समीक्षा करके अपने-अपने क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगायेंगे।

समीक्षा तो हमेशा से होती आई है और यदि यूं ही होती रही तो शराब भी यूं ही अवैध रूप से बिकती रहेगी। प्रत्येक थाना व उसकी चौकियां तो इसकी रोक-थाम के नाम पर जो 'धंधा' कर रही हैं, वही सब क्राइम ब्रांच की तमाम चौकियां भी कर रही हैं। इस रोक-थाम के नाम पर वे तमाम अधिकारी जम कर लूट कमाई करने में जुटे हैं। दिखावे के तौर पर कागज़ी कार्रवाई करके ये लोग अपने-अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। कार्रवाई के नाम पर होता यह है कि तमाम थाने व चौकियों वाले, अवैध धंधा करने वालों से फ़ोन करके केस मांग लेते हैं। अर्थात पुलिस वाले अवैध शराब पकड़ने के जो मुकदमे दर्ज करते हैं वे सब फ़र्जी होते हैं। यानी कि शराब का अवैध कारोबारी अपने किसी कारिंदे को दो-चार बोतलों के साथ पुलिस के हवाले कर देता है, जिसे वह अदालती कार्रवाई के बाद छुड़वा लेता है।

यदि सीपी साहब वास्तव में ही इस धंधे को बंद करना चाहते हैं तो यह कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। इसके लिये सबसे पहले फ़र्जी पर्चे देने का काम बंद करवाना होगा। इन्हीं फ़र्जी पर्चों को आगे रखकर पुलिस कह देती है कि हम क्या करें, देखिये हमने तो इतने पर्चे दे दिये व इतनी शराब पकड़ ली, अदालत इनको सस्ते में छोड़ देती है तो हम क्या

विकास अरोड़ा पुलिस आयुक्त :
कृष्णपाल भक्ति में हो गये लीन?

करें? दरअसल कोर्ट भी बखूबी समझती है इन फ़र्जी पर्चों का खेल। यदि इस खेल में सजायें कड़ी हो जायें तो पुलिस के भाव और भी बढ़ जायेंगे।

इसकी रोक-थाम का बड़ा सरल सा उपाय है कि जिस थाना व चौकी क्षेत्र में इस तरह का धंधा पकड़ा जाये तो सम्बन्धित एसएचओ एवं चौकी इंचार्ज को इस के लिये दोषी मानकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये। क्राइम ब्रांच की जो फोर्स आज शराब कारोबारियों से पर्चे मांगते फ़िरती है वह इस धंधे को छोड़ कर थाने व चौकियों की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाए।

अगला महत्वपूर्ण मसला पकड़े गये दोषी थानेदारों के खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही करने का है। यहां आकर, सज़ा दे सकने वाले उच्चाधिकारी दबाव में आ जाते हैं। यदि कोई भ्रष्ट है तो लेन-देन करके मामले को निपटा देगा और यदि ईमानदार एवं सख्त मिजाज का है तो राजनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक देगा। जहां एक-दो बार ऐसा हुआ तो सारी योजना एकदम से औंधे मुंह गिरना तय है।

अभी पिछले दिनों सीपी साहब ने थाना डबुआ के एसएचओ सोहनपाल गूजर को लाइन हाजिर किया था। जाहिर है कि उन्होंने यह कदम उसके निकम्मे व भ्रष्ट आचरण को देख कर ही तो उठाया होगा। लेकिन, बमुश्किल एक हफ्ता भी सीपी साहब उसे लाइन में न रख पाये। उसे लूट कमाई के हिसाब से ज़िले का बेहतरीन थाना सूरजकुंड सौंप दिया गया। यह वही थाना है जहां से होकर शराब तस्कर भारी मात्रा में अपना माल दिल्ली सप्लाई करते हैं। कहने को सीपी साहब कुछ भी कह सकते हैं लेकिन समझने वाले बखूबी समझते हैं कि इस तैनाती के पीछे केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर का हाथ है।

**जहां थानेदारों को यह पता हो कि सीपी के पल्ले कुछ नहीं है, वे अपनी तैनातियां एवं सेवाकाल मंत्रियों एवं विधायकों के सहारे भली प्रकार से काट सकते हैं तो वे सीपी की क्या परवाह करेंगे? इसी के चलते सारी पुलिस व्यवस्था लुंज-पुंज हो चुकी है। यदि यह व्यवस्था दुरुस्त हो तो किसी थानेदार के इलाके में किसी बदमाश, अपराधी, तस्कर आदि की क्या मजाल जो जरा भी पंख फड़फड़ा सके।**

समझने वाली बात यह है कि जिस पुलिस के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जनता ने अपने प्रतिनिधियों को सत्ता सौंपी है व खुद ही उसके भ्रष्टाचार में शामिल हो गये। इसलिए इस भ्रष्टाचार के लिए राजनेता भी पूरी तरह से जिम्मेदार है।

# स्वास्थ्य मंत्री विज नेहरू निर्मित एम्स में भर्ती

अनिल विज नेहरू!

**दिल्ली ( म.मो. )** बीते सात साल से हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं का इस तरह बेड़ा गर्क कर दिया है कि उन्हें अपने खुद के इलाज के लिये दर-दर भटकना पड़ रहा है। करीब डेढ साल पहले जब इनकी टांग टूटी थी तो इलाज के लिये मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए। गत वर्ष कोरोना होने पर अपने तमाम बड़े-बड़े सरकारी अस्पताल छोड़ कर गुड़गांव के मेदांता में आकर भर्ती हुए। इसी सप्ताह ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो जाने के चलते काफ़ी गंभीर स्थिति में दिल्ली के उस एम्स अस्पताल की शरण में आए जिसका निर्माण 1956 में जवाहर लाल नेहरू ने कराया था।

विज महोदय तो चंडीगढ़ से चलकर उस एम्स में आकर झट से भर्ती हो गए जिसमें भर्ती होने के लिये लोग वर्षों तक इन्तजार करते रहते हैं। उनसे कोई पूछे कि राज्य के वो गरीब, लाचार लोग अपना इलाज कराने कौन से अस्पताल में जायें? ड्रामेबाज़ी के तौर पर विज साहब राज्य के अस्पतालों में यदा-कदा छापेमारी की नौटंकी तो करते रहते थे परन्तु उन अस्पतालों में न तो बड़े पैमाने पर खाली पड़े पदों को कभी भरने की सोची और न ही आवश्यक दवाओं एवं उपकरणों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया।

जिस जवाहर लाल नेहरू को विज समेत तमाम भाजपाई पानी पी-पी कर कोसते हुए देश का बंटाधार करने का दोषी ठहराते हैं, उसी नेहरू के बनाये अस्पताल की बजाए वे अटल बिहारी वाजपेयी या मोदी द्वारा बीते सात सालों में बनाए गए किसी एम्स में क्यों नहीं गये? वैसे भी इन लोगों को अस्पतालों की कोई खास जरूरत तो होनी नहीं चाहिये क्योंकि इनके पास लाला रामदेव द्वारा निर्मित एक से एक बेहतरीन कोरोनिल जैसी दवायें मौजूद हैं। वैसे तो इसकी भी क्या जरूरत है, जिस गौ मूत्र व गोबर के इस्तेमाल की सलाह जनता को देते हैं उसी का इस्तेमाल खुद भी कर लेते। झज्जर के इलाके में कांग्रेस राज में जो एम्स अस्पताल बनाया गया था, उसमें बीते सात साल में विज की सरकार ने रत्ती भर भी काम आगे नहीं बढ़ाया। इतना ही नहीं 2019 के चुनावों से पहले जनता को बेवकूफ़ बनाते हुए नारनौल के इलाके में जिस एम्स का शिलान्यास खट्टर जी ने किया था आज तक एक ईंट भी नही लगी। उन्हीं दिनों में भिवानी-हांसी रोड पर स्थित गांव प्रेम नगर की बीसियों एकड़ पंचायती ज़मीन अस्पताल बनाने के नाम पर कब्जाई थी उसका भी यही हाल है।

समझा जा सकता है कि अस्पताल के नाम पर जनता को लारे-लप्पे देकर बहकाने में ये लोग माहिर हैं। वास्तव में इन्हें अस्पताल आदि बनाने में कोई रुचि नहीं है। इनके अपने इलाज के लिये तमाम पंचतारा निजी व सरकारी अस्पताल जो मौजूद हैं।